Postal Registration No. G/CHD/0107/2012-14 RNI No. CHABIL/2000/3469

हिन्दी/अंग्रेजी मासिक पत्रिका

दीन बन्धु सर छोटूराम

जाट लहर

जाट सभा, चण्डीगढ़ के सौजन्य से प्रकाशित

वर्ष 14 अंक 06 30 जून, 2014 मूल्य 5 रुपये

प्रधान की कलम से

पुलिस प्रशासन अव्यवस्था बनी मानवाधिकार हनन की व्यवस्था

डा. महेन्द्र सिंह मलिक

मानवाधिकार हनन कोई नई व्यथा-कथा नहीं है बल्कि युग-युगांतर से चली आ रही एक कालिमा है। 'यथा राजा, तथा प्रजा' की कहावत से हर कोई वाकिफ है। कहा जाता है ''पावर करप्टस ए परसन' पुलिस का गठन भी एक डंडे वाली शक्ति के रूप में हुआ था। अंग्रेजों को राजस्व वसूली हेतू एक डंडा शक्ति की जरूरत थी तथा 1861 में एक अधिनियम के तहत पुलिस का गठन हो गया। आज के राजनेता भी पुलिस से ऐसे ही कार्य करवा रहे हैं। हालांकि सभी कर्मी बुरे आचरण के नहीं होते। तालाब को एक गंदी मछली ही गंदा कर देती है। अगर 1000 कर्मियों में 2 कर्मी किसी दबाव या मजबुरी बाद मे आदतन कुछ गलत करते हैं तो धब्बा पूरी फोर्स पर ही आएगा तथ्यों से ज्ञात होता है कि जहां पुलिस ने तश्दद किए, बलात्कार किए या एक पक्षीय फैसले लिए वहीं पुलिस पर गलत आरोप भी लगे।

वर्ष 2011 में राष्ट्र में पुलिस कर्मियों के विरूद्ध 61765 शिकायतें आई और 21672 केस दर्ज किए गए जिनमें से 21144 के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की गई, 282 केसों में मजीस्ट्रीयल जांच तथा 246 में जुडीशियल जांच स्थापित हुई। इस तरह 35 प्रतिशत केसों में जांच शुरू हुई तथा 28789 यानि 46 प्रतिशत शिकायतें अप्रमाणित या गलत साबित हुई। ऐसे ही 1229 कर्मियों को ट्रायल हेतू भेजा गया जबकि 475 मसले हल हुए या वापिस ले लिए गए। हालांकि मामला वापिस लेने में भी पुलिस का दबाव होता है। कुल 26536 केसों में 21144 केसों में हुई विभागीय जांच में 8500 केस वापिस लिए गए और 15090 कर्मियों के विरूद्ध जांच पूर्ण हुई तथा 873 कर्मियों को सजा हुई या सेवा से निकाल दिया गया।

अक्सर पुलिस पर नकली एन्काउंटर, तशदद तथा एक्सट्राशन के मुद्दे ही मानवाधिकार हनन में शामिल होते हैं। वर्ष 2011 में ऐसे 72 केस दृष्टिगोचर हुए जहां पुलिस कर्मियों की दखल अंदाजी थी, 46 कर्मियों को चार्जशीट किया गया। मानवाधिकार हनन में सबसे उपर दिल्ली राज्य है। यहां 50 केस सामने आए, उड़िसा में 7, आसाम तथा उत्तर प्रदेश में 5 केस प्रत्येक में हुए हैं।

एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2001 से 2010 तक 14231 व्यक्ति पुलिस या जुडीशियल कस्टडी में मरने के केस दर्ज हैं केवल पुलिस हिरासत में इस अवधि में 1504 हताहत हुए। ऐशियन मानवाधिकार केंद्र ने कहा कि 99.99 प्रतिशत पुलिस कस्टडी मृत्यु हिरासत के 48 घंटे के दौरान ही हो गई थी तथा करीब सभी केस पुलिस प्रताड़ना तथा मारपीट के ही हैं। सर्वाधिक पुलिस हिरासत में मृत्यु के केस महाराष्ट्र में 250, उत्तरप्रदेश में 174, गुजरात में 134, आंध्रप्रदेश में 109, बंगाल में 98, तमिलनाडू में 95, आसाम 84, पंजाब में 57, मध्यप्रदेश में 55, हरियाणा में 45, बिहार में 44, केरल में 42, झारखंड में 41, राजस्थान में 38, ओडिसा में 34, दिल्ली में 30, छत्तीसगढ़ में 24, तथा उत्तराखंड में 20 हिरासत में मृत्यु केस दर्ज हुए। जम्मु काश्मीर विश्वविद्यालय के सर्वेक्षण के अनुसार केवल जम्मु काश्मीर में 8000 से 10000 तक व्यक्ति पुलिस हिरासत में लापता हुए हैं। पुलिस हिरासत में मृत्यु, पुलिस प्रताड़ाना, पुलिस द्वारा बाहरी दबाव में किए जाने वाली निरंकुश कार्यवाही के कई मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा सही आंकड़े नहीं दर्शाए जाते जिस कारण आम आदमी न्याय से वंचित रहता है। जन साधारण की मौलिक हितों की रक्षा के लिए भारत द्वारा वर्ष 1997 में संयुक्त राष्ट्र प्रताड़ना विरोधी संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे लेकिन आज तक भी इनको प्रमाणिक तौर से लागू नहीं किया जा सका।

राजनेता भी ऐसे मामलों में भली भूमिका नहीं निभाते। बलात्कार जैसे घिनौने अपराध में मुलायम सिंह यादव ने 'लड़कों से गलतियां हो जाती हैं' कहकर तेल ही दिया। क्या ऐसा ही आचरण किसी लड़की द्वारा किए जाने पर समाज उसे अपनाता। कुछेक पंचायतें भी तुगलकी फरमान देने में किसी से पीछे नहीं हैं।

आज सोच का विषय तो प्रशासनिक लाचारी है। केस होते हैं पकड़े जाते हैं, सामाजिक तथा प्रशासनिक दबाव में किसी रूतबे या बेईजती के डर से दबाए भी जाते हैं। बड़े आदमी को शर्मिंदगी से बचाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाएं जाते हैं, उनमें राजनैतिक तथा प्रशासनिक दोनों ही हो सकते हैं। आज रक्षक ही भक्षक की भूमिका में है। थानों में बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में मन कराह उठता है कि आम जन किसे फरियाद करे, किस पर भरोसा करे।

खुद ही कातिल, खुद ही रहबर, खुद ही मुनसिब ठहरे।
अकरबां मेरे करें खून का दावा किस पर।।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन तो कर दिया गया लेकिन उस द्वारा दिए गए सुझाव आज भी गौण हैं। वर्ष 1979-81 में आठ सुझाव दिए गए थे। सुरक्षा कमीश्न का गठन, पुलिस चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, बदली में कम से कम अवधि निर्धारण, राजनेताओं तथा बाबूओं द्वारा अपना बर्चस्व स्थापित करने हेतू मनमानी बदलियों पर

-शेष पेज 2 पर

'k"k i;t &1

रोक, पुलिस एज़्ट 1861 में सुधार एवं बदलाव लेकिन हालात जस के तस हैं। आज राजनीति का अपराधिकरण हो चुका है और पुलिस बल उनके प्रभाव से अछूता रह नहीं सकता तथा राजनीति दो धारी तलवार बनकर पुलिस का दुरूपयोग तथा हतोत्साहित करती रहती है। न्यायिक प्रक्रिया में शिथलता से भी अपराध बढ़ते हैं। अपराधी कानून दाव पेंच में जीत जाते हैं। 1951 में 6 लाख 25 हजार केस न्यायालयों में लंबित थे 2003 में इनकी संज़्या 17 लाख से अधिक हो गई। कुल 55 लाख अपराधों में से 35.8 लाख अपराध स्थानीय तथा विशेष धाराओं में दाखिल किए गए। संसद की स्टैडिंग कमेटी ने बताया कि आज गृह प्रशासन के 25 मिलियन केस विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। आतंकवादी तथा संगठन अपराधों को राजनैतिक प्रक्षय मिलता। माओवादियों तथा आतंकवादियों को बंगाल, उज़र प्रदेश, पंजाब, जज़्मू काश्मीर ज़्या पूरे राष्ट्र में राजनैतिक प्रक्षय है तथा पुलिस पर छींटाकशी होने से बल हतोत्साहित हाते हैं और रंग में रंगने में ही भलाई मान, मनमानियां करते हुए हर तरह के अपराध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भागीदारी कर बैठते हैं।

सामाजिक ताने-बाने को अस्त-व्यस्त करना, धमकाना, आंतकिंत करना और प्राणियों की हत्या, बलात्कार, कार्यो में बाधा, अपहरण और भय का माहौल कायम करना ही आतंकवाद, माओवाद और मानवाधिकारों के हनन व अवहेलना की श्रेणी में आता है। विडंबना यही है कि मानवाधिकार सरंक्षण हेतू बने कायदे-कानून और नियमों की अवहेलना करने वाले ही सबसे अधिक मानवाधिकारों की दुहाई देते हैं और उन्ही कानूनों के तहत बचाव की दुहाई देते हैं जिनकी उन्होने अत्याधिक अवहेलना की होती है और उनको परोपकार भी जाति, धर्म,समुदाय, दल और राजनैतिक सरंक्षकों के रूप में मिल जाते हैं जबकि पीड़ितों के मानवाधिकारों के हनन की किसी को चिंता नहीं।

विश्व के अन्य राष्ट्रों में भी मौलिक अधिकारों के हनन के इलावा जातीय रंग भेदभाव, निष्पक्ष सुनवाई, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, सामाजिक आर्थिक अधिकारों का हनन, रिफ्युजी अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार, महिला विरूद्ध भेदभाव आदि के आधार पर मानवाधिकारों का उग्घन होता है। सोमानिया, अफगानिस्तान व पाकिस्तान से सैंकड़ों प्रवासियों को महिनों तक हगरी की जेलों में बंद रखा गया। वर्ष 2012 में युनान में न्यायालय द्वारा एक विशाल जलूस में भाग लेने पर दो व्यक्तियों को पांच व चार साल की सजा सुनाई गई। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन जैसे विकसित देशों में भी इस प्रकार के मानवाधिकारों के उग्घन के मामले उजागर हुए हैं लेकिन इनके द्वारा समय पर किए गए प्रभावी व ठोस प्रयास मानवाधिकारों के हनन की रोकथाम में काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं।

कमजोर पुलिस व प्रशानिक व्यवस्था के कारण आज राष्ट्र में महिलाओं के विरूद्ध अपराध, अत्याचार, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, बच्चों पर जुल्म इत्यादि मानवाधिकारों के हनन की घटनाएं दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं। हर घंटे तीन महिलाओं से बलात्कार के केस उजागर हो रहे हैं। वर्ष 2007 से 2011 के दौरान राष्ट्र में महिला यौन शोषण/अत्याचार व बलात्कार की क्रमशः 201099 व 311077 घृणित मामले उजागर हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली महिला के विरूद्ध अपराधों में राष्ट्र में सबसे अग्रणीय है, आंध्रप्रदेश में 60 प्रतिशत से अधिक महिलाऐं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। आज महिलाऐं घरों में भी सुरक्षित नहीं है। इसका मुज़्य कारण पुरूष प्रधान समाज की प्रवृज़ि है उसकी मानसिक प्रवृज़ि को जगाना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले हमें भ्रूण हत्या, दहेज हत्या पर अंकुश लगाना होगा। आज लिंग अनुपात लगातार कम हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 20 वर्षों में करीब एक करोड़ कन्या भ्रूण हत्याएं हुई हैं।

पूरे विश्व में महिलाओं के मानवाधिकारों सबसे अधिक हनन होता है। विशेषतर भारत वर्ष में हरियाणा, राजस्थान, उज़र प्रदेश आदि में नगर निगम, पंचायती राज संस्थाओं में चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों की जगह पर उनके पति, लड़के या निकट संबंधी आमतौर पर कार्यवाही को अंजाम देते हैं और महिला प्रतिनिधियों की जगह ख़ुद ही स्थानीय स्तर की पंचायतों व बैठकों में हिस्सा लेते हैं। विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र का ये भी दुर्भाग्य है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में महिलाओं की संज़्या केवल 10.8 प्रतिशत ही है। राज्य सभा में यदि महिलाओं की इस स्थिति पर नजर डालें तो तथ्य है कि 233 राज्य सभा सांसदों में महिलाओं की संज़्या केवल 21 है।

युनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार आज भारत में 80 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और 8 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिन्होने 5वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया। प्राईमरी स्तर पर 27 प्रतिशत व 12वीं स्तर पर 41 प्रतिशत बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसके इलावा 40 प्रतिशत लड़किया तो अधर में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं। विश्व के कुल 20 करोड़ बाल श्रमिकों में से 5 करोड़ से भी ज्यादा भारत में ही हैं। इससे स्पष्ट है कि देश के होनहारों को उचित शिक्षा व पालन पोषण के अधिकारों के प्रति प्रशासन कितना गंभीर है। केंद्रीय सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कर रहीं है लेकिन आज भी भारत में एक तिहाई आबादी यानि कि 42 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। वर्ष 2011 में भारत का भुखमरी में 88 देशों की सूचि में 73वां स्थान था और विकास की दृष्टि से राष्ट्र का विश्व में 136वां स्थान है जो कि जनता के जीवन यापन के मौलिक अधिकार पर करारा प्रहार है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2 करोड़ बाल श्रमिक काम करते हैं जबकि गैर सरकारी ऐजेंसियों के अनुसार यह संज़्या 6 करोड़ है और स्कूल के बाहर यानि शिक्षा से वंचित रहने वाले बच्चों को मिलाकर यह संज़्या 10 करोड़ बनती है। फ्री ट्रेड संघों की अंतर्राष्ट्रीय कनफैडरेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 से 10 वर्ष

की आयु के 60 प्रतिशत बच्चे कृषि, उद्योग व वाणिजय क्षेत्रों में श्रम करते हैं। इस प्रकार आज राष्ट्र विश्व का सबसे बड़ा बाल श्रम उद्योग बन गया है और समस्त विश्व से कार्यकारी श्रमिक बच्चों की 30 प्रतिशत संज़्या केवल भारत से है। मानवाधिकार हनन में राजनैतिक दलों की भी अह्म भूमिका है। गत पांच वर्षों में विभिन्न राजनैतिक दलों के 260 उज़्मीदवारों ने स्वंय घोषणा की कि उनके विरूद्ध महिला अपहरण, यौन शोषण, अत्याचार आदि के मामले दर्ज हैं जिनकी पृष्ठभूमि मानवाधिकार हनन और अपराधिक थी। आज देश की संसद में 543 सांसदों में से 186 सांसद मानवाधिकार हनन या अपराधिक पृष्ठभूमि से हैं जिनमें से 112 के खिलाफ हत्या, आक्रमण, महिला विरूद्ध अपराध व अपहरण जैसे संगीन अपराधिक मामले दर्ज हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में संसद व विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले 62847 उज़्मीदवारों में से 11063 अपराधिक छवि के जन प्रतिनिधि बनने में कामयाब हुए हैं और इनमें से 5233 के खिलाफ तो बेहद गंभीर अपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर इस प्रकार की अपराधिक पृष्ठभूमि वाले जनप्रतिनिधि चुने जाते रहे तो आम आदमी के मानवाधिकारों की रक्षा होना कठिन हो जाएगा।

आज राष्ट्र के लिए अन्न पैदा करने वाले किसानों के अधिकारों का सर्वाधिक हनन हो रहा है। केंद्रीय व राज्य सरकारों की किसान विरोधी नीतियों के कारण राष्ट्र का पेट भरने वाले किसान के अस्तित्व को भी खतरा बन चुका है। देश में 18 हजार किसान कर्ज के बोझ व भुखमरी के कारण प्रतिवर्ष ज़ुदकशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। इससे भी अधिक इस भोले इंसान की कृषि भूमि अधिग्रहण कर औद्योगिक घरानों को कौड़ियों के भाव पर उपलज़्ध करवाई जा रही है और वह उन्ही कारखानों में मजदूरी करने को मजबूर है। ज़्या उनका मानवाधिकार नहीं है? अधिगृहित भूमि के मालिकों को मिलती है जिगत। किसानों को हक नहीं आत्म हत्या का उपहार मिल रहा है लेकिन उस पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं। राष्ट्र की 75 प्रतिशत ग्रामीण भोली जनता सरकारी उपेक्षा व अनदेखी के कारण अपने कुशल स्वस्थ जीवन के अधिकार से वंचित हो चुकी है जिसको स्वच्छ पेय जल तक की जन स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलज़्ध नहीं हैं।

सेना तथा अर्ध सैनिक बलों पर भी अपहरण, गुमशुदगी अपराध के किस्से उजागर हो रहे हैं। ऐसे केसों में 235 सेना अधिकारी शामिल पाए गए जिनमें दो मेजर जनरल, तीन बिगेडीयर, 9 कर्नल, 3 लैफ्टीनैंट कर्नल, 111 अर्ध सैनिक बलों के अधिकारी, 111 पुलिस अधिकारी तथा 31 आतंकवादियों की संलिप्तता पाई गई हैं। मानवाधिकारों का रक्षक सूचना का अधिकार एक दिखावा ही रह गया है। राजनैतिक दल इससे भी पला झाड़ चुके हैं। सार्वजनिक हित के मामलों की सूचना को राष्ट्रीय सुरक्षा कवच पहनाकर जबाबदेही से मुक्त किया जा रहा है।

मानवाधिकारों की रक्षा से ही कानून का शासन स्थापित करने हेतू प्रयास जरूरी है जिनकी अवहेलना की किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय के डी के बासु बनाम बंगाल सरकार 1997(1) केस में दिशा निर्देशों की अनुपालना - ''जब कभी भी मानव सज़्मान को जज़्मी किया गया, सज़्यता एक कदम पीछे हट गई, प्रत्येक ऐसे अवसर पर मानवता का झंडा झुक जाता है'' जरूरी है। आज पक्षपात रहित पुलिस बल की आवश्यकता है। हमारे पास नज़्सलवादियों तथा स्थानीय आतंकी गुटों के लिए निःशुल्क पोषक स्थल हैं। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को अपनी पद-दलित जनता की दशा का उत्थान करने के लिए शांति, व्यवस्था और आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित पुलिस सुधारों तथा सामाजिक-आर्थिक सुधारों को लागू करने में दृढ़ होना चाहिए। मानवाधिकारों का पालन करने की आवश्यकता की अवहेलना नहीं की जा सकती ज़्योंकि हर समय व स्थान पर 'कानून के शासन' को कायम रखना है। देश के सभी राज्यों को अपने-अपने क्षेत्र में मानवाधिकार आयोग स्थापित करने चाहिए। मैं 'काम्नवैल्थ मानवाधिकार सुत्रपात' के निदेश श्री माया दारूवाला के इस कथन से सहमत हूं कि अच्छा अधिकार/ नियंत्रण आंतकवाद का खात्मा करने में सहायक हैं। अतः किसी को पीड़ा पहुंचाना आतंकवाद को कुचलने का अस्त्र नहीं है।

मानवाधिकार सरंक्षण अधिनियम 1993 में आवश्यकतानुसार प्रयाप्त संशोधन करके वैध दंडाधिकारी सज़ा के साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापित किए जाएं और सभी राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जाए और जिला न्यायालयों को मानवाधिकार न्यायालयों के नाम दिए जाएं जिससे मानवाधिकारों के उल्घन से संबंधित जुर्मों का भी शीघ्रता से निपटान सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचारों को रोकने व पुरूष बाहुल्य समाज की दिमागी सोच को बदलने हेतू एक सामाजिक आंदोलन की तुरंत प्रभाव से शुरूआत जरूरी है। निर्दोष जनता को मानवाधिकारों के उल्घन की मार से बचाने के लिए लोकतांत्रिक राजनीति/आजादी, सिविल स्वाधीनता एवं धार्मिक सहनशीलता को हर अवस्था में सुरक्षित रखना होगा। पुलिस बलों व राजनैतिक दलों में बढ़ रहे भ्रष्टाचार एवं अपराधीकरण पर नियंत्रण करना आवश्यक है। आज प्रत्येक जिला स्तर पर मानवाधिकारों से संबंधित मामलों के निपटारे हेतू विशेष अदालतें स्थापित करने की भी आवश्यकता है। लेखक स्वंय मानवाधिकार एवं कानून के विशेषज्ञ हैं।

डा0महेन्द्र सिंह मलिक
आई0पी0एस0(सेवा निवृत)
पूर्व पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य चौकसी ज़्यूरौ प्रमुख, हरियाणा
प्रधान, जाट सभा चंडीगढ़ एवं
अखिल भारतीय शहीद सज़्मान संघर्ष समिति

Agenda of Economic Development for the New Prime Minister

Ram Niwas Malik - 9911078502

ShiriNarenderModi becomes the 15th Prime Minister of India on 26.05.2014 at a time when both Indian economy and governance are in total mess and disarray. The country is riven with many serious problems. GDP growth has come down to 4.6%. Fiscal deficit is 4.47% (Rs. 5.09 crore) of GDP. Internal debt is 37.2% (Rs 42,12,575 crore) of GDP. Current account deficit is 1.7% of GDP. The cumulative loss of Air India is more than Rs. 30,000 crores. Other airlines are also bleeding red. Jet Airways suffered a loss of Rs 2154 crore in the quarter ending March 2014. Inflation and unemployment rates are soaring. Investment climate is not salubrious. Therefore the alround scenario in the country is very depressing. On the other hand, Chinese economy is still growing at 7%. In fact, the rise of NarenderModi at this point of time is like the Phoenix from the ashes. Therefore by becoming the Prime Minister of India, MrNarenderModi has worn a crown full of thorns. On the other hand, the Indian voter has also become aspirational, transactional and unforgiving. He has built a mountain of hopes from the new Government and will not hesitate to berate it if his hopes are not answered or fulfilled in the foreseeable future, particularly in the fields of controlling inflation and unemployment. According to Rajesh Srinivasan, Gallup's (a polling organization) research director for Asia says," It is very dangerous to create expectations and not meet them". Given the horrific poverty and terrible inequality in India, the youth is impatient for the early return of good days in the near future as promised by the Prime Minister during his election speeches. Otherwise all that the modern youth needs today is a match-stick event. Stephen P. Cohen, an American thinker is right when he says," Conflicts over water, ethnic and linguistic tensions and the pressures of widening income disparities all threaten India's stability from within. Yet other than the Maoist uprisings in eastern India, these issues are generally relegated to the bottom of the threat hierarchy ". The new Prime Minister must realize this harsh reality. Today every knowledgeable voter switches his TV set in the evening to find out what new decisions the new Prime Minister has taken during the day.

The unwritten mandate for any Government is to eradicate poverty from the map of India. It is eradicable within the next decade if the government is determined to do so and has prepared a precise road map for economic resurgence of the country. As on today (67 years after independence), 40 crore people are wallowing in harsh poverty conditions. Almost an equal number living just above the poverty line, called marginally poor, are also struggling in life. Remaining 45 crore people constituting middle and upper middle class are also living in non-congenial environment because of omnipresent insanitation, polluted air and dishonest dealings called corruption. So only saints may be leading a peaceful life in upper Himalayas.Root cause of unending or ever expanding poverty and other associated problems is the failure of successive Governments to control the population explosion which at present is rising at the rate of 18 million people (equal to one Australia) every year. As a matter of fact, all the economic and socials ills are born out of this malady. By now, India would have been a prosperous country had its population been controlled to 700 million people. No Government on earth can tackle poverty problem of India till it tapers its population growth to zero percent within the next decade.

Therefore the first job of the present Prime Minister (which no other PM did in the past) is to draw and roll out a precise road map for eradication of poverty and improve two other important parameters simultaneously i.e. Human Development Index and ease of doing business in India. India occupies 135th place in the International ranking in these two parameters.The basic philosophy behind the road map should be to attain a fast track economic growth such that India supersedes China by 2025 in terms of the size of the national economy. This document should not merely harp on the single parameter of achieving 9% growth of GDP. The growth scenario should be accompanied by two more factors i.e. distribution of new found wealth to all the strata of society (inclusive growth) and increasing the level of sanitation in all the streets of India. Till now we don't have even 10 cities which may boast of 100% sewerage system. The billion dollar question on everybody's mind, "When India will be free from poverty and called a developed country !". This should be the sole motto of the new Government and the vision document should provide an answer to this starred question.

By far India should have been much ahead of other nations. China during the 1950-60 period was way behind India. It was Deng Xiaoping who strictly enforced the one child policy and large scale economic reforms to open up the Chinese economy in 1974. The race against time (in economic build-up) started thereafter. For the next thirty years, mainland China delivered the fastest-growing economy in the world. Before his death, Deng could claim to have lifted more people out of poverty than any other leader in human history. China is a closed society with an open mind whereas India is an open (Democratic) society with a closed mind. This attitudinal diversity makes the difference between two big economies hanging at different levels.India is a country with fabulous wealth and fabulous poverty.Now you can see the difference between two countries. To give one example, China took only six years to build the 18200 MW 3- Gorge dam whereas the capacity addition by NHPC is only 7000MW since 1983. Still all is not lost yet. Foreigners still perceive vast untapped potential of economic dynamism in India and they want Indian democracy to bloom vis-a-vi-vis China. A stable Government has arrived after many years and let us hope and pray that it rises to the occasion this time to

develop a strong and vibrant India and herald the promised good days very soon. One wishes that the new Prime Minister plays the role of Deng Xiaoping. In other words, the Government or the entire Parliament must have a burning desire to take India ahead of China by 2025.

Indian voter desperately wants results in the following five areas:

1. Promotion of employment opportunities so that an educated youth gets a reasonably good job to live a decent life.
2. Lowering the sale price of essential commodities.
3. Prevention of adulteration in food-stuffs.
4. Improvement of delivery of service from the in-place infrastructure like hospitals, schools etc. Quality of education is now inversely proportional to the expansion of educational institute.
5. Eradication of Poverty and raising of sanitation level.

I have framed a 30-point program which will answer all the five aspirations of the Indian voters:

1 By 2017 reduction of fiscal deficit to 2% of GDP.

2 Reduction of Current Account Deficit to 0.5% of GDP. A special cell should be created to advise government how to bring record FDI in India by dismantling trade barriers .

3 Reduction of debt on power utilities (read the statement of power companies of Delhi before the Supreme Court on 19.05.2014). The total amount of bad debts for all the power utilities in various states amounts to Rs. 3.0 lac crores.

4 Reduction of N P As on banks. The total amount of bad loans is Rs. 5 lac crores.

5 Reduction of debt on state Governments and Central Government. The debt on West Bengal government is Rs. 2.25 lac crore. The state government is paying an annual interest of Rs. 25000 crore. Hardly any amount is left for development projects. The trend in some of the states to make regular payment of interest to the bankers and keep the principle amount outstanding indefinitely also constitutes financial indiscipline.

6 Improving the level of sanitation and Human Development Index of the people of India. Scope of the term, " sanitation " is very wide and does not simply relate to providing sanitary latrines in villages. It means total cleanliness in the local rural and urban environment including 100% sewerage system in urban areas and recycling of waste products. As a matter of fact, a new ministry should be set up for recycling of waste products. Accordingly launching of National Senitation Program (NSP) will give a new brand value and look to India. Only then India will be truly called "Incredible Shining India".

7 Promoting the level of ease of doing business in India. Presently she occupies 135th rank-in the table of 189 nations.Also wage a war against drug menace and increasing obscenity in films and media.

8 Controlling price rise of essential commodities, particularly vegetables and pulses.The problem of vegetable shortage by promoting vegetable farms in 7 N-E States ,Chattisgarh and MP and extending ApniMandi concept in all the towns.

9 Water resources and Hydro-power development in various river basins of India. Brahamputra river basin alone has the potential of generating 75,000 MW of power. The state of M.P. alone can feed whole of India if the entire agricultural land is brought under irrigation and mechanized farming.Development of hydro power and Nuclear power plants is the key to prevent growing dependence on thermal power plants. India cannot survive without developing additional hydra power to the tune of 1.0 lac MW within next 15 years.

10 Expansion of Railway network and convert it into a major engine of growth for Indian economy. The immediate requirement is to electrify and double 18,000 kms of railway track. Railway Ministry has become a behemoth organization and needs urgent downsizing. The best way to achieve this objective isto allow the state governments to run the trains within the respective states. Railway Ministry should run only inter-state trains. The Freight Corridor project should be declared as Sunflag or Flagship project of India.Total electrification of Railway network will save huge amount of diesel consumption.Special scheme is also needed to fully utilize the under utilized railway tracks.

11 Massive increase in Infrastructure Development in core areas (roads, power plants, cement and steel factories, drainage and ports). Revive Bharat Nirman Program and accomplish the same within next two years.

12 Reforming FCI and prevent the decay of food-grains for want of adequate storage capacity.Presently wheat production in India is more than the consumption . Export of wheat will take place only if improved seed varieties are developed and introduced.

13 Cut down the consumption of crude oil and reduce the heavy import bill (of 160 mt of crude oil) costing Rs. 10 lac crore annually (9% of GDP) and explore new avenues of oil and gas aggressively in India and abroad. Only one discovery has been operationalized so far from the blocks allotted under 9 NLEPs. This program will be the key to India's economicssecurity.ONGC and GSPC should be given the best blocks separately for exploration of oil and gas.

14 To mine adequate amount of coal to feed all the thermal power plants.

15 Bringing revolution in the development of solar energy and wind energy. Solar cooking and water heating can save huge amount of cooking gas and power.Sloar power should be developed to the tune of 50000 MW in the desert areas of Rajasthan and Gujarat by 2020.

16 Controling population explosion to ensure zero growth rate by 2020. The issue of population explosion has taken the shape of a time bomb which can explode any time

during the next decade. Demographic disaster can be converted in to demographic dividend only on papers.

17 Development of Tourism hot-spots particularly in North-Eastern States. Reduction of road distances with the help of tunnel roads in hill states will greatly boost tourism.

18 Splitting biggers state like U.P. into smaller states (or set up sub-capitals within the states) to improve the level of administration. U.P. state is of the size of a very big country and it can not be run efficiently and effectively on the existing model. The right size of an efficient state is equal to 20 constituencies of Lok Sabha and bigger states like Maharashtra should be re-organized. U.P. will never progress till it is split into three states because a Chief Minister cannot rule a state of the size of a big country under existing political structure.

19 Developing dairy development and horticulture hubs in seven N-E States. These states can bring white revolution in India very soon.

20 Economic participation in African countries on the pattern of China.

21 Decongestion of over-crowded cities along with strict implementation of urban renewal program. Setup 100 new intelligent cities in different states. Also to introduce modern Mass Transport System like Delhi Metro Railway System in all the major cities of India to get rid of the daily traffic snarls.

22 Setting up of SEZs and new growth centers along the 100 new smart cities to ensure a big bang in industrial development. Also to setup intelligent industrial parks along the coastal areas to tempt foreign companies to setup their units in India, the way China attracted Taiwanese manufactures to Shanghai SEZ. Creation of special Central Environment Authority is urgently needed for fast track clearance of projects and not repeat the POSCO and other stories. Renuka dam project in Himachal is waiting forest clearance for the last six years. Also a special scheme needs to be introduced to improve the infrastructure level of the existing industrial parks in the country. Remodel the new Land Acquisition Act to facilitate early acquisition of land for important infra structure projects.

23 To take up special program in irrigation and agriculture development in areas(Vardha and Yavatmal districts of Maharashtra) where farmers are committing suicides.

24 To take special development work programs in Naxalite infested areas. Infrastructure development id the best anti-dote to the growth of Naxalism.

25 To take special economic activities in highly underdeveloped districts like Kalahandi and Saputara in Odisha and Gujarat states respectively.

26 To launch a strict program for controlling adulteration of food-stuffs, milk products and medicines. Adulteration of food-stuffs has became a very serious health hazard requiring urgent attention and action.

27 Reframing poverty alleviation programs and doling out direct cash to BPL families to prevent huge amount of leakage of funds. However the welfare schemes should be linked with family planning practices adopted by the BPL families.

28 To create a special cell to monitor the level of delivery of services from existing infrastructure like hospitals, colleges and universities.

29 India's Geology offers a remarkable resource bounty (mineral wealth). Therefore it is very essential to create a special authority to regulate the mining and export of minerals to earn huge amount of foreign exchange. Cracking on illegal mining is the immediate need of the hour as this is a sure step to nullify the adverse impact of Current Account Deficit.

30 To set up a high grade scientific research institute to help in the indigenous production of large scale defense equipment. This institute should also act as a Think Tank for overall skill development and promotion of innovative ideas. All the State Govts. and Central Ministries be directed to curb the huge expenditure on publicity. The Govt. of India spent Rs. 187 crore on the publicity of Bharat Nirman Program alone.

All these issues are very knotty and require patience for their solution. It will be good strategy to pluck low hanging fruits first. Development of solar energy for heating, cooking and power requirements is one such ripe fruit to give very early returns. Launching of National Sanitation Program is another. Issue of controlling fiscal deficit is the most difficult task. This is because MNREGA and Food Security Bill schemes involve huge expenditure (Rs. 2.5 lac crore) and even 50% money doesn't reach the poor. These two schemes need to be converted into a single social security net for the poor whereby a sum of Rs. 200 lac crore should be directly sent to 8 crore BPL families through banks. This system will totally choke the leakage of funds in the process. However this doll out should be stringed to family planning measures being adopted by the BPL families. Mr. Ruchir Sharma clearly tells in his famous book, " Breakout Nations" that financial system collapsed only in those countries who could not control the three metrics i.e. fiscal deficit, current account deficit and debt to GDP ratio within the prescribed limits. These limits exceeded mostly in those economies where money was spent more on welfare schemes and less on infrastructure projects. Accordingly fiscal prudence and discipline are the need of the hour to save Indian economy.

Therefore the new Prime-Minister needs to urgently discuss these issues with the Secretaries and advisors of the government and draft a pragmatic road map for the economic development and then address the nation accordingly. This 30-point program encompasses all the issues of economic development, GDP growth and unemployment. There is no other short-cut to achieve this holistic objective. Therefore the Government needs to adopt and implement this program sincerely and strictly to make India the elusive economic power house and supersede China by 2025. The country has the strength to achieve this feat by 2025 and there is no doubt about it.

हर सांस में समाई है शहीदों की याद

lj tHkku nfg;k

जाटलैंड त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। जाटों के लिये इससे अधिक गौरव का विषय क्या हो सकता है कि जब भी समय की पुकार हुई जनमानस ने अपने रक्त से इतिहास का सृजन कर दिया। इसे जनइतिहास कहते हैं। जाटलैंड में असंख्य शहीदी गांव है और यह पावन भूमि अंसख्य शहीदों की जन्मदाता है। उन्होंनें मानव कल्याण हेतु अपने आपको स्वतः ही समर्पित कर दिया। आइये जन इतिहास को जानने के लिये उन गांव में चले जहां पर न जाने कितनी मानव संघर्षों की श्रृंखलाओं की विरासत विद्यमान है। पर इतिहास के पन्नों से गायब है। समर्पण एवं वीरत्व इस धरती के लिये नई चीज नहीं है इसकी एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि है। जब इसे महार्षि क्षेत्र में वैदिक संस्कृति तेजी से विकास की और अग्रसर थी, महाराजा पृथु माधता जैसे चक्रचर्ती नरेशों ने सरस्वती के पावन तीर्थों पर ही राजसूर्य यज्ञ और अश्वमेघ रचाये थे। महाभारत का युद्ध भी इसी वीरभूमि का विशेवय है। महाभारत के बाद भी यहां के निवासियों ने सदा अन्याय, अत्याचार एवं धर्मान्ध के विरूद्ध आवाज उठाई एवं कुरबानियों का सिलसिला जारी रखा। अपनी धरती के लिये जान पर खेलना जाटलैंड के लोगों के खून में हैं। यहां का गबरू दिलेरी से जूझकर लहुलुहान होता है फिर कुरबानी पर गर्व से मुस्कराता है। जाटलैंड में शहीदों के किस्सों में लिपटी उनकी यादें आज भी इस छोर के गांव से लेकर उस छोर के गोव तक प्रेरणास्वरूप प्रवाहित हो रही है। जाटलैंड ने अपनी महानगरी दिल्ली में कितने साम्राज्यों का का उत्थान–पतन देखा है। हुकमतें आई और मिट गई, पर दिल्ली के चारों ओर बसे जाट क्षेत्र के वासियों ने अपनी संस्कृति और सामाजिक परम्पराओं को कायम रखा। इसके लिये उन्हें कई बार भारी मूल्य भी चुकाना पड़ा है पर हमें यही प्रेरणा मिलती रही – कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी और हर जुबान पर यही शब्द रहे– ''हारया नर वो जाणिये जो कहे हार की बात''

''चाँदनी चौंक'' दिल्ली की शान जाट बहादूरों की वीरता वसुधरा है जहां आज भी शहीदों के खून की लाली दमक रही है। घरों मे हमेशा शहीदों की पौध उगती रही है। हमें पता है कि इतिहास हमेशा बहादूरों के लिखे जाते है और हम यदि चाँदनी चौक के सन्दर्भ में इतिहास का आवलोकन करें तो हमें अपने वीरों की शहादत पर गर्व है।

चाँदनी चौंक दिल्ली में गुरूद्वारा शीश गंज है तथा 1857 की जनक्रान्ति का शहीदी स्मारक भी है। दोनों ऐतिहासिक स्थल जाटकुरबानी को बयान करते हैं। चलो गुरूद्वारा शीशगंज को शहादत से शुरू करते है। सन् 1675 में औरंगजेब के हुक्म से गुरूतेगबहादुर जी को चाँदनी चौंक में शहीद कर दिया तथा उनका शीश और धड़ अलग–अलग शहीदी स्थल पर पड़े थे। इस जुल्म के पश्चात वहां सन्नाटा था परन्तु औंरगजेब के जुलम के सामने कोई आवाज उठााने की हिम्मत नहीं उठा पा रहा था। परन्तु गुरू जी के शरीर का अन्तिम संस्कार तो करना ही था। लालकिले के सामने कुछ व्यापारी अपनी बैलगाड़ियों के साथ इस त्रास्दी को देख रहे थे। अंतिम संस्कार हेतु कुछ सिखों ने उनसे सम्पर्क किया परन्तु औरगंजेब के सिपाहियों के जुल्म से वे अति भयभीत थे। उनमें एक व्यापारी किसान मादी गांव (नारनौल, हरियाणा) का गौदां था। उसने गुरू जी के शरीर को वहीं से उठाने का साहस किया। वह शहीदी स्थल पर गया तथा घास फूंस से अपने शरीर को ढ़ककर अपने आपको खंजर घोप डाला वह मृत्यु को प्राप्त हो गया तथा चारों ओर उनका शहीदी रक्त फैल गया। दो सिख बहादुरों ने गुरू जी के शीश तथा धड़ को वहां से उठा लिया। औरगंजेब के सिपाहियों को यह अहसास नहीं हो पाया तथा वे गौंदा बहादुर के पड़े शरीर को ही गुरू जी का शरीर समझते रहे। लखीशाह बंजारा ने गुरूजी के धड़ को वर्तमान बगंलासाहब गुरूद्वारा नई दिल्ली के स्थल पर अग्नि को समर्पित करके गुरू के शरीर का दाह संस्कार कर दिया। दूसरी ओर भाई जैता जी गुरूजी के शीश को लेकर सानीपत जिले के गांव बड़खालसा पहुंचें तथा रात एक जाट परिवार के घर बिताई। जाट परिवार ने बड़े सम्मान के साथ जैता जी की सेवा की तथा गुरूजी के शीश की रात भर सुरक्षा की। प्रभात होने से पूर्व भाई जैता को जाट परिवार के लोगों ने कोसों दूर तक सुरक्षा देकर गन्तव्य तक पंहुचने का साहस दिया तथा अन्ततः गुरूजी का शीश आनन्दपुर साहब पहुंच गया।

इस घटना क्रम का जब औरंगजेब के सिपाहियों को पता चला तो वे भयभीत हो एवं आवेश में आ गये। उस समय औरगंजेब दक्षिण में था। औरंगजेब के आने से पूर्व सिपाहियों ने इस घटना को दबाने के सभी प्रंबध किये। बड़ खालसा के जाट परिवार के सभी सदस्यों का कत्ल कर डाला परन्तु गुरू जी की कुरबानी को वे पहले ही सम्मान दे चुके थे। जाट कौम को इस प्रकार की कुरबानी देने को सदैव सौभाग्य प्राप्त रहा है।

हम एक ऐतिहासक अभूतपूर्व क्षण के साक्षी हैं। लोककल्याण के लिए आत्मत्याग करने वालों में हमारे पूर्वज महार्षि दधीचि से लेकर आजतक न जाने कितनी जाट विभूतियां हुई है पर क्या हम इन की शहादतों को जन जन तक पहुंचा पाये हैं?

प्राचीन वैदिक भू–क्षेत्र जाटलैंड में सृष्टि काल से शिमहाराज की गणी व्यवस्था प्रचलित रही है जिसमें जन ही शक्ति रही है और जन ही इतिहास रहा है। सदैव जन साधारण ने ही मातुभूमि (भारत मात) संस्कृति (वैदिक संस्कृति) व मातृभाषा की रक्षा की है। जनशक्ति ही सदैव यहां प्रभावी रही है अतएव इस शक्ति को इतिहास के पन्नों में लाना ही सही इतिहास ी परिभाषा है। क्या हमें यह आभास नहीं होना चाहिये कि शीशगंज चांदनी चौंक गुरूद्वारे का इतिहास गौंदा जाट व बड़ खालसा जाट परिवार की शहादत का भी इतिहास है। क्यों हमारे इस गौरवशाली शहादत को इतिहास के पन्नों से गायब कर रखा है? हमें इस त्रुटि को सुधार कर सही इतिहास बयान करना होगा।

हमें गर्व है कि गुरू तेगबहादुर की शहादत की स्मृति में शीशगंज गुरूद्वारा बना हुआ है। यहीं पर 1857 के स्वतंत्रता

संग्राम के महानायक अश्वमेघी बल्लभगढ़ नरेश नाहर सिंह ने भी 9 जनवरी 1858 को शहादत दी थी। फांसी का फंदा चुमते हुये 36 वर्षीय सिंह ने कहा था ''दीपक बुझा न पाए'' चाँदनी चौंक में राजा नाहर सिंह की समाधि तो है पर वहां पर स्वतन्त्रता लाठ का निर्माण क्यों नहीं? वहां तो स्वतन्त्रता ज्वाला ज्योति प्रज्जवलित रहनी चाहिये यही है चाँदनी चौंक की असली विरासत।

दीपक की लौ तो भगत सिंह ने बुझने नहीं दी। निःसन्देह जाटों को राष्ट्रीय भावनाओं का कलश पंरम्परागत तौर पर अपने पूर्वजों से मिला है। जब कभी राष्ट्रीय सेवा का आह्वान हुआ है जाट सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़े मिले हैं। नेताजी सुभाष ने जब कहा 'दिल्ली चलो' का जयघोष किया तो हजारों जाटों ने आजादहिन्द फौज को सुशोभित किया। आजादहिन्द फौज के एक सिपाही मेहर सिंह ने अपनी आखिरी ऐतिहासिक रागनी में राष्ट्रीय भावना का गहरा रंग छोड़ा।

''साथ रहणिया संग के साथी दया मेरे पे फेर दियो
देश के ऊपर जान झोंकदी लिख चिठ्ठी में गेर दियो।
एक बात तै या भी लिख दो मत उल्टा कदम हटाइयो रै
जिस जननी का दूध पीलिया मत रण में आण लजाइयो
कह मेहर सिंह प्रोण त्याग कै कर दुयमन को ढेर दियो
साथ रहणिया संग के साथी.....''

आजादी के बाद देश ने पांच युद्धों का सामना करना पड़ा। इनमें कोई 10 हजार जवान वीरगति को प्राप्त हुये। इनमें सबसे ज्यादा शहादत देने वाले जाट जवान थे। लिखने का तात्पर्य यह है कि जाटों की वीरता व शहादत का बरवान मनुस्मृति से आजतक निरंतर होता रहा है। तो प्रश्न अब यही उठता है कि क्या हम भारत के इतिहास को चाटूकरों के हाथों में रहने दें–हमें तो सही इतिहास का बरवान करना ही होगा और शहीदों की चिताओं पर मेले लगाने ही होगें तभी भारत का जन (जनसाधारण) देश अधिनायक बनेगा।

Railway Budget-2014

To
The Editor
Jat Lehar Chandigarh

The railway budget -2014 is as insipid as it was last year. A good budget should clarify two issues. Firstly it should tell the status of ongoing projects and the new projects to be taken up to meet the targets projected in the 12th Five Year Plan document and the Vision document of the Railway Ministry prepared two years ago. Secondly the budget should indicate the total requirements of funds , their availability and management, The basic philosophy of the Indian Railway (IR) network is to electrify the entire track length by 2025 and increase the share in passenger traffic and freight movement to the extent of 50 % and save the consumption of diesel oil worth Rs. 1lakh crore annually . There is no mention of this commitment in the budget . Introduction of 58 super fast trains does not constitute a good budget. The budget lacks boldness and is only a litany of familiar platitudes. Mr. Gowda puts entire reliance on FDI and PPP model for executing new projects.PPP model has failed in India. Look at how people are breaking the Toll-Tax barriers. The budget is also silent maladies plaguing the IR. Some of these are as bellow.1) IR has become a behemoth organisation and needs radical restructuring / downsizing as mentioned in the Presidential address.2) Presently only 35% of railway tracks (24000 kms) are electrified and doubled. The most pressing need is to electrify and double the tracks at the rate of 5000 kms per year against the present rate is only 200 kms .3) A large percentage of tracks remains under utilised. For example ,only one train runs along the newly laid Rohtak-Rewari railway line. This problem can be solved only if the states are allowed to lay their own railway links and run trains within their territories. For example a railway link of 25kms between Ukalana and Narwana can connect the Sirsa -Hissar section with Delhi -Chandigarh railway line.These three steps if implemented urgently , can r revolutionise the IR. Kindly publish this letter in the columns of your esteemed newspaper.

Yours
Sincerely,
Ram Niwas Malik
Engineer-in-Chief (Retd.)
E1/5, Gurgaon.
9911078502.

भरतपुर जाट राजवंश के आधार स्तम्भ

jkd'k ljkgk

भरतपुर के इतिहास में वीर चुरामन का नाम बहुत ही सुन्दर ढंग से लिखा गया है। वह पहला योद्धा था जिसने जाटों को संगठित कर जहां शक्ति का सृजन किया वहीं देश में पहली बार स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर भावी भरतपुर जाट रियासत की नींव डाली जिसे राजा बदन सिंह ने अपनी दुरदर्शिता से सिंचित किया तथा इसका विस्तार किया तथा बाद में महाराजा सूरजमल ने अपने असीमित साहस, पराक्रम और दुरदंशिता से उत्तरी भारत में एक प्रचण्ड शक्ति के रूप में खड़ा किया तथा इस रियासत की सीमाओं का विस्तार करके मुगलों तथा मराठों के सामने जाट शक्ति का दबदबा कायम किया । भरतपुर के जाट राजवंश के शासकों में वीर जवाहर सिंह व महाराजा रणजीत सिंह का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है उन्होंने भरतपुर पर प्रभावशाली ढंग से शासन किया तथा भरतपुर के जाट राजवंश को चार चांद लगाये इसके अतिरिक्त भरतपुर के राजवंश के प्रमुख शासक ये हुए है। महाराजा रतन सिंह, महाराजा केहरी सिंह, महाराजा रणधीर सिंह, महाराजा बलदेव सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा किशन सिंह तथा महाराजा वृजेन्द्र सिंह परन्तु इन सब शासकों में भरतपुर रियासत के मुख्य आधार स्तम्भ ठाकुरबदन सिंह तथा महाराजा सूरजमल ही थे। जिनका नाम भरतपुर के जाट राजवंश के शासकों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है।

Bkdqj cnu flag ¼1723&56½ % ठाकुर बदन सिंह ने अपने राजनैतिक जीवन की शुरूआत जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह के सामन्त के रूप में की थी। ठाकुर बदन सिंह के विनम्र ओर शिष्ट व्यवहार से सवाई जय सिंह प्रभावित थे इसलिए उन्होंने बदन सिंह के सिर पर टीका लगाकर उन्हें राजा की पदवी से विभूषित किया तथा मथुरा, वृंदावन, महावन, छाता और होडल परगनों की जागीरें भी ठाकुर वदन सिंह को प्रदान कर दी। 1725 में सवाई जय सिंह ने ठाकुर बदन सिंह को उसके प्रशासनिक परगानों का प्रशासन स्थाई रूप से हस्तान्तरित कर दिया ठाकुर बदन सिंह शान्ति प्रिय शासक था उसमें सैनिक प्रतिभा का अभाव होते हुए भी वह साहसी और दूरदर्शी था। 1725 में ठाकुर बदन सिंह ने अपनी राजधानी केरूप में डीग मेकं किला, बगीचे और महलों का निर्माण करवाना आरम्भ कर दिया जो उस शताब्दी के अंत तक ही चलता रहा इसके अतिरिक्त उनके समय में कुम्हेर, भरतपुर और बैर के दुर्गो का भी निर्माण आरम्भ किया गया। ठाकुर बदन सिंह का पुत्र सुरजमल बड़ा योग्य सेनानायक था। उनके शासनकाल में सेना का संचालन व संगठन का कार्य सुरजमल के हाथों में ही रहा। बदन सिंह ने महाराजा जयसिंह का विश्वासपात्र बनकर जहां अपने क्षेत्र और प्रभाव को बढ़ाया वहीं उन्होंने सम्पन्न ओर प्रभावशाली परिवारों से वैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित किये। 1729 में सवाई जय सिंह ने फरीदाबाद, पलवल और मेवात की राहदारी वसूलने का अधिकार भी बदन सिंह ने दिलवा दिया। बदन सिंह ने अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र व शकित का भरपुर विस्तार किया परन्तु अपने नेत्र रोग के कारण दीर्घकाल तक शासन का कार्य नहीं कर सके तथा बीस साल शासन करने के पश्चात इन्होंनें अपने शासन के सारे अधिकार अपने पुत्र सुरजमल को सौंप दिये थे। ठाकुर बदन सिंह का 7 जून 1756 को डीग के महल में देहान्त हो गया तथा इस प्रकार एक वीर, दुरदर्शी तथा साहसी शासक के युग का अनत हुआ।

egkjktk lwjey ¼1756&1763½ %& सूरजमल का जन्म सन् 1707 में ठाकुर बदन सिंह के पुत्र के रूप में हुआ था। ठाकुर बदन सिंह का उतराधिकारी सूरजमल का शरीर मध्यम दर्जे का तथा सुंगठित था। उसमें अपने मूल वंश के सभी गुण थे उसमें स्फूर्ति, साहस, वीरता, चालाकी, दुरदर्शिता तथा संगठन क्षमता के सभी गुण विद्वमान थे। जिस समय ठाकुर बदन सिंह की मृत्यु हुई उस समय सुरजमल की आयु अधिक नहीं थी। उतराधिकार सम्भालने के पश्चात सूरजमल ने सर्वप्रथम कार्य जाट जाति में अपने आपको स्थापित करने का किया था। सवाई जय सिंह जाट कुंवर सूरजमल को अपने पुत्र के समान स्नेह करते थे। महाराजा जय सिंह ने मरने से पूर्व सूरजमल से यह वचन लिया था कि तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह की ओर जयपुर की गद्दी की सदैव रक्षा करोगे। सूरजमल ने भी इस सम्बन्ध में राजा जय सिंह को पूर्ण आश्वासन दिया था। 21 सितम्बर 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण वह अवसर भी आ गया जब सूरजमल द्वारा दिये गये अपने वचन का निर्वाह करना पड़ा। सवाई जय सिंह की मृत्यु के पश्चात वंश परम्परा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह का राज्यभिषेक किया गया परन्तु माधों सिंह ने अपने बड़े भाई ईश्वरी सिंह के राज्यभिषेक को सीधे चुनौती दे दी तथा जोधपुर, बुंदी तथा कोटा के शासको ने भी माधोसिंह का समर्थन कर दिया। इन हालात में ईश्वरी सिंह ने सूरजमल को अपनी सहायता के लिए बुलाया। 20 अगस्त 1748 को गहरू नामक स्थान पर दोनों सेनाओं का मुकाबला हुआ। यह लड़ाई चार दिनों तक चली जिसमें सूरजमल ने अद्भूत वीरता का परिचय देकर मराठों का मनोबल तोड़ दिया। मजबूर होकर होल्कर को ईश्वरी सिंह के सामने शान्ति का प्रस्ताव रखना पड़ा इस प्रकार इस युद्ध के माध्यम से राजा ईश्वरी सिंह को न्याय मिला तथा माधों सिंह को पूर्व में मिले पांच परगानों से सन्तोष करना पड़ा।

इस युद्ध ने राजा सूरजमल की प्रतिष्ठा को चार चाँद लगा दिये इसकी बहादुरी से प्रभवित होकर अब अन्य शासक भी इनसे सहायता की अपेक्षा करने लगे राजा सूरजमल के नेतृत्व में जाटों की शक्ति का सभी लोग लोहा मानने लग गये थे इस समय का लाभ उठाकर राजा सूरजमल ने भी जाट राज्य की सीमा का विस्तार किया तथा मुगलों से तथा मराठों से लोहा लिया। राजा सूरजमल ने राजनैतिक विवाहों के द्वारा अपने राज्य का विस्तार करने की अपने पिता बदन सिंह की नीतियों का भी अनुकरण किया। उन्होंनें अपना विवाह होडल के एक शक्तिशाली व सम्पन्न जाट प्रमुख चौधरी काशीराम की पुत्री किशोरी बाई से किया इस प्रतिभाव रानी का नाम भरतपुर के इतिहास में मुख्य रूप से पढ़ने को मिलता है। भरतपुर का इतिहास इस बात का

गवाह है कि दुरदर्शी, साहसी और कुशल राजनीतिज्ञ रानी किशोरी बाई ने अपने उचित निर्णय तथा प्रशासनिक कुशलता से भरतपुर की साख को अनेकों बार गिरने से बचाया था। महाराजा सूरजमल ने अपने जीवन में कठिन से कठिन हालातों में कभी हार नहीं मानी तथा अनेक युद्धों में वीरता, अद्भूत शौर्य, पराक्रम, दुरदर्शिता तथा कुटनीति का प्रदर्शन करके युद्धों में सफलता प्राप्त की तथा भरतपुर जाट राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। ठाकुर बदन सिंह की मृत्यु के पश्चात जाट राज्य को यदि किसी ने मजबूती के साथ विस्तार किया तो उसमें पहला और अन्तिम नाम महाराजा सूरजमल का आता है। उन्होंनें भरतपुर का विशाल अजेय दुर्ग ही नहीं बनवाया बल्कि अनेक दुर्ग, गढिया, भवन तथा बगीचों का भी निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त उस समय के भंयकर युग में भी मुगलसत्ता तथा मराठों को चुनौती देते हुए एक लोह स्तम्भ की भांति अडिग खड़े रहे। एक सुगठित सैना तथा अपनी चतुराई की सहायता से महाराजा सूरजमल ने अपने राज्य का विस्तार किया उनकी मृत्यु के समय उनके राज्य में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, आगरा, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मथुरा, होडल, पलवल, गुडगांव, बल्लबगढ़, अलीगढ़ हाथरस तथा दिल्ली के आसपास का क्षेत्र शामिल था। सूरजमल ने अपने पीछे एक ऐसा विस्तृत राज्य छोड़ा था जहां शान्ति और समृद्धि का शासन था। 25 दिसम्बर 1763 को महारजा सूरजमल की मृत्यु के पश्चात भी उनके जाट शासकों ने भरतपुर राजवंश की वपंश प्रणाली के अन्तर्गत भरतपुर पर शासन किया परन्तु उनके शासन काल में भरतपुर का जाट साम्रज्य शनै–शनै कमजोर होता चला गया। वीर जवाहर सिंह व महाराण रणजीत सिंह तथा महारानी किशोरी के प्रयासों व कार्यों को भी भरतपुर के राजवंश के इतिहास में भुलाना सम्भव नहीं है। जिन्होंनें भरतपुर राजय को मजबूती प्रदान करने के लिए अद्भूत साहस, दूरदर्शिता व वीरता का परिचय दिया था।

List of Donors of Jat Sabha Chandigarh

Sh. Partap Singh s/o Sh. Banwari Lal	# 447, Sector 2, Panchkula	5100.00
Major Sandeep Sangwan	# 629, Sector 16-D, Chandigarh	5100.00
Sh. Dev Raj Dahiya	# 276/28, West Ram Nagar, Sonepat	5100.00
Ashwani Duhan	Ram Nagar Colony, Arya Samaj Road, Jind	5100.00
Sh. P. S. Malik, IFS (Rtd.)	# 464, Sector 2, Panchkula	5000.00
Sh. Anil Kadyan	# 720, Sector 23, Sonepat	5100.00
Sh. Pardeep Singh Tomar	VPO: Gudhan, Distt. Rohtak	5100.00
Sh. Naresh Bhanwala	# 3881, Urban Estate, Jind	5100.00
Sh. Gurvinder Singh Phor	VPO: Shekhpura Khalsa, Distt Karnal	5100.00
Sh. Daya Nand s/o Sh. Sahib Singh	VPO: Shekhpura Khalsa, Distt Karnal	5100.00
Sh. Ajit Khatkar s/o Sh. Kanwar Bhan Singh	VPO: Shekhpura Khalsa, Distt Karnal	5100.00
Sh. Naresh Phor s/o Sh. Partap Singh	VPO: Shekhpura Khalsa, Distt Karnal	5100.00
Sh. Surjeet Singh s/o Sh. Jaswant Singh	VPO: Shekhpura Khalsa, Distt Karnal	5100.00
Sh. Savtantra Dagar s/o Sh. Ajit Singh	VPO: Baghru, Distt. Sonepat	5100.00
Sh. Yadvender Kharb s/o Sh. Ved Singh	# 1339, Urban Estate, Jind	5100.00
Sh. Rajesh Sihag s/o Sh. Bharat Singh	# J-174, May Filed Garden, Sector 51, Gurgaon	5100.00
Sh.Naresh Kundu s/o Sh. Kishan Singh	# 994, Sector 3, Rohtak	5100.00

स्त्री का स्वाभिमान

राजा सुशांत सिंह एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। वह अक्सर वेश बदलकर अपनी प्रजा का हालचाल जानते रहते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि उनके राज्य में रहने वाली एक महिला का पति गलत संगति में पड़ गया है और नाराज होकर महिला ने अकेले रहना शुरू कर दिया है। महिला के पास रोजगार का कोई नियमित साधन नहीं था, इसलिए उसका जीवन कठिनाई में बीत रहा था। राजा वेश बदलकर उस महिला के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, 'देवी, आप अत्यंत कठिनाई में अपना जीवन गुजार रही हैं। क्या आप बेसहारा हैं? यह सुनकर स्त्री चौंककर बोली, 'आपसे किसने कहा, मैं बेसहारा हूं। मैं बिल्कुल बेसहारा नहीं हूं।' इस पर राजा बोले, 'पर आप रहती तो अकेली हैं' महिला बोली, 'अकेले रहने का यह अर्थ नहीं है कि मैं बेसहारा हूं। मेरे तो तीन–तीन सहारे हैं।' राजा ने पूछा, 'आपके तीन सहारे कौन हैं? क्या मैं उनका नाम जान सकता हूं।' महिला बोली, बिल्कुल जान सकते हैं। मेरे दोनों हाथ, मेरा धर्म और मेरा ईश्वर मेरा सहारा हैं। अब आप ही बताइए जिस महिला के पास जगत के सबसे बड़े सहारे मौजूद हों, वह बेसहारा कैसे हो सकती है? महिला के इस जवाब ने राजा को निरूतर कर दिया। वह गर्व से बोले, जिस राज्य में आप जैसे स्वाभिमानी और कर्मठ महिला रहती हो, वह राज्य धनी है। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने आपको बेसहारा कहा। फिर उन्होंने उस महिला को अपना सही परिचय दिया। उन्होंने उस महिला को अपने महल की रसोई का कार्यभार संभालने का काम सौंप दिया।

WOMEN OF HARYANA ARE BEST IN THE WORLD

R.K. Malik, Senior Advocate

I have seen almost whole world and realized that women of Haryana are best in the world. 99% women of Haryana don't smoke nor drink. Even 99% girls of Haryana voluntarily transfer their property share to their brothers. Although, I have not heard that any brother has transfer his property share to his brother whose financial position is weak but 99% girls of Haryana even if their financial position is weak still voluntarily transfer their property share to their brothers.

In the month of June, 2014 I was in England and I came to know that in England 20% girls give birth to the child without marriage and even for this action, the Government provide them free house and also give financial assistance as if they have done some noble cause. In England, 60% women have solemnized more than one marriage. Only 20% women in England can only say that they have only solemnized one marriage. I have not seen any English lady who was not smoking or taking drink.

One Indian living in England was telling that one English boy is doing service with him and he was telling that one day he came on job in a taxi driven by his present father who is presently husband of his mother and he has charged full rent from him which he was charging from other passengers.

One day, I was talking to Englishman and I have brought to his notice that in my state i.e. Haryana, 99% ladies don't touch the wine nor they smoke and they don't even think regarding divorce even in their unconscious mind. Even if their financial position is weak still they transfer their whole share of property voluntarily in the names of their brothers. Even 100% work of home is performed by the ladies in Haryana and in the said home work even she doesn't take the assistance of her husband. The said Englishman remarked that I don't believe that such standards women are still on the earth. I asked him, if it is true that such standard women are in Haryana how you will grade them and his remarks were that if it is true that such types of women are still there in some states, they are God.

So, I will requests to the men of Haryana that there is no need to go in temple; Devis are residing in their house. Give full respect and affection to them.

वैवाहिक विज्ञापन

- SM 4 Jat Girl (12.9.87) 27/5'3.5" M.Com, B.Ed. From MDU. Currently teaching Accounts & Business in a reputed school at Rohtak. Father retired from Air Force, Owner of three acre land and own house & plot in village. Avoid Gotras: Dagar, Kharb, Suhag, Cont.: 08053108405
- SM 4 Jat Girl(11.11.85) 29/5'6" M.A (History) from Delhi University. Pursuing P. Phil from Delhi University and getting Scholarship Rs. 5000/- PM. Father MCD (civil) Contractor, Brother Manager in Food Corporation of India. Avoid Gotras: Chhikara, Suhag, Ruhil, Cont.: 09873244677
- SM 4 Jat Girl (13.7.90) 24/5'8" M.A (Economics) Working in a reputed private Company. Avoid Gotras: Hooda, Malik, Khatri, Cont.: 09417529417
- SM 4 Jat Girl 26/5'6" Economics Hons. MBA, Working in AXIS Bank at Gurgaon with Rs. 6.5 Lac PA. Mother Associate Professor, Brother Income tax Inspector. Avoid Gotras: Deswal, Malik, Lather, Cont.: 09996149490
- SM 4 Jat Girl 31/5'5" MCA, MBA, NET, Ph.d. Employed as Director in Engineering College, Palwal. Avoid Gotras: Saharan, Hooda, Malik, Cont.: 09813730434, 01257-277179
- SM 4 Jat Girl 24/5' MA (History), BEd., Pursuing P Phil from Punjab University Chandigarh. STET (PGT) qualified. Father Haryana Govt. Employee at Panchkula. Avoid Gotras: Rangi, Kuhar, Rana, Solanki, Tomar, Gehlan, Cont.: 09467507715
- SM 4 Jat Girl 25/5'2" Chemical Engineer from P.U. (B.Tech.) Employed in Reliance Company in Vadodra (Gujrat) with 6.5 lac package, Avoid Gotras: Lohchab, Bajaad, Hooda, Dhankar, Cont.: 08146991568, 09803450267
- SM 4 Jat Girl 26/5'3" MCA, MBA, Employed as supervisor in Central Govt. on contract basis. Avoid Gotras: Bagri, Nehra, Nain, Cont.: 09417415367
- SM 4 Jat Boy 24/5'9" Employed as Clerk in Excise & Taxation Deptt. Haryana Government. Agriculture land 18 acres. Avoid Gotras: Kadyan, Jakhar, Jatrana, Cont.: 09466352484
- SM 4 Jat Boy 28/5'11" Employed as 2nd Officer in Merchant Navy. Qualified for Chief Officer. Avoid Gotras: Kaliraman, Maan, Cont.: 09781506097
- SM 4 Jat Boy 28/5'11" B.Sc.(Marine Engineering) Convent Educated. Working in Indian Navy, Avoid Gotras: Kadyan, Malik, Tokas, Cont.: 09466203446, 08679157130
- SM 4 Jat Boy 25.6/6'1" M. Tech from PEC, Employed as Lecturer in a private College at Panchkula. Father Govt. Officer. Own House at Panchkula. Avoid Gotras: Kundu, Maan, Dhul, Cont.: 09417869505
- SM 4 Jat Boy 26.6/5'9" BS.c Computer Science Employed as Assistant in Govt. Job., Avoid Gotras: Puniya, Solath, Jhajra, Cont.: 09467782712, 09888887312
- SM 4 Jat Boy 24/6' Employed as Constable in Chandigarh Police, Avoid Gotras: Dahiya, Malik, Pawaria, Cont.: 09417567383
- SM 4 Jat Girl 27½ years B.Tech, Based MNC Engineer Package 12 Lacs P.A., Gotra : Nandal, Hoods, Lakra, Cont.: 9915805679

जाट सभा चंडीगढ़ द्वारा आन दी स्पाट निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित

जाट सभा चंडीगढ़ द्वारा 4 जुलाई 2014, आज ज्ञानदीप वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सैक्टर 20 चंडीगढ़ के इलावा हरियाणा रा%य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों-चौ० भरत सिंह यादगार खेल स्कुल, निडानी जिला जींद, भाई सुरेन्द्र सिंह मलिक यादगार कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कुल निडानी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जुलाना जिला जींद, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शामलो कलां जिला जींद, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लजवाना कलां, जिला जींद, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गतोली जिला जींद, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल जुलाना जिला जींद, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किला जफ़रगढ़ जिला जींद, ज्ञानदीप माडल स्कुल सैक्टर 18 पंचकुला व भवन विद्यालय सैक्टर 15 पंचकुला पर आयोजित की गई भाई सुरेन्द्र सिंह मलिक यादगार अखिल भारतीय आन दी स्पाट निबंध लेखन प्रतियोगिता में हरियाणा व चंडीगढ़, मोहाली के विभिन्न कालेजों व स्कूलों के लगभग 1500 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

जाट सभा द्वारा यह प्रतियोगिता हर वर्ष सभा के प्रधान डा० एम०एस०मलिक आईपीएस (सेवा निवृत) के दिवंगत बहु प्रतिभाशाली पुत्र की यादगार में आयोजित की जाती है जो कि स्कूलों व कालेजों के विद्यार्थियों में शैक्षणिक व सांस्कृतिक गतिविधियों के विस्तार के प्रति रूची उत्पन्न करने के इलावा उनको अपनी प्रतिभा तथा विवेक द्वारा लेखन कला व शैक्षणिक दक्षता का प्रदर्शन करने का अवसर भी प्रदान करती है।

सभा के प्रधान व हरियाणा के पूर्व पुलिस महा निदेशक एम०एस०मलिक आईपीएस (सेवा निवृत) ने चौ० भरत सिंह यादगार खेल स्कुल, निडानी जिला जींद व भाई सुरेन्द्र सिंह मलिक यादगार कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कुल निडानी केंद्रों पर निबंध के आन दी स्पाट विषय - 'बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एवं बढ़ती कीमतें वर्तमान सरकार के समक्ष अह्म समस्याएं हैं अथवा 'नशीली दवाईयों का दुरूपयोग समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अथवा मनोरंजन की बजाए दूरदर्शन अनुदेश तथा सूचना का मुख्य माध्यम बन गया है' की घोषणा करते हुए प्रतियोगिता का शुभारंभ किया सारिका मलिक, ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर पंचकूला ने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जुलाना जिला जींद, केन्द्र में प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया तथा ज्ञानदीप वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सैक्टर 20 चंडीगढ़ केंद्र पर श्री अभिषेक मलिक द्वारा इस रा%य स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। परीक्षार्थियों को हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में निबंध लिखने की छूट प्रदान की गई और प्रतियोगिता को ग्रामीण व शहरी दो श्रेणियों में विभाजित किया गया।

इस प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के विशेषज्ञों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के बाद की जाएगी और परिणाम समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के इलावा प्रतियोगियों को डाक द्वारा भी प्रेषित किया जाएगा। प्रतियोगिता के विजेताओं को 24 फ़रवरी 2015 को बंसत पंचमी तथा स्वतंत्रता पूर्व के समय के किसान तथा गरीब वर्ग के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध नेता दीन बंधू सर छोटु राम की 133वीं जयंती समारोह के अवसर पर जाट भवन चंडीगढ़ में सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर्ता को 3100 रूपये व स्वर्ण पदक, द्वित्तीय व तृतीय स्थान पाने वालों को क्रमश: 2100 रूपये नकद व रजत पदक तथा 1500 रूपये नकद व कांस्य पदक देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक श्रेणी में 1000 रूपये, 900 रूपये तथा 700 रूपये व 600-600 रूपये के दो सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। इस प्रतियोगिता का सारा खर्च 'भाई सुरेन्द्र सिंह मलिक यादगार स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान निडानी' जिला जींद द्वारा वहन किया जाता है।

सम्पादक मंडल

संरक्षक : डा. एम.एस. मलिक, आई.पी.एस. (सेवानिवृत)
सम्पादक : श्री गुरनाम सिंह, आई.एफ.एस. (सेवानिवृत)
सह-सम्पादक : डा॰ राजवन्तीमान
साज सज्जा एवं आमुख : श्री आर. के. मलिक
प्रकाशन समिति : श्री बी.एस. गिल, मो० : 9888004417
श्री जे.एस. ढिल्लो, मो० : 9416282798
वितरक : श्री प्रेम सिंह, कार्यालय सचिव, जाट भवन, चण्डीगढ़

जाट भवन 2-बी, सैक्टर 27-ए, चण्डीगढ़
फोन : 0172-2654932 फैक्स : 0172-2641127
Email : jat_sabha@yahoo.com

मुद्रक प्रकाशन एवं सम्पादक गुरनाम सिंह ने जाट सभा, चंडीगढ़ के लिए एसोशियटिड प्रिन्टर्ज़, चंडीगढ़, फोन : 0172-2650168 से मुद्रित करवा कर जाट भवन, 2-बी, मध्यमार्ग, सैक्टर 27-ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित किया।